



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62991

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8961 वर्ष 2026

वाहिद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुनील कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक वाहिद की ओर से थाना कोतवाली नगर, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 50 वर्ष 2026, धारा 21/22 एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 130 ग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद होने की बात कही गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 50, 52-क और 42 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है और

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे आज दाखिल पूरक शपथ पत्र में स्पष्ट किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 19.2.2026 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी रेखांकित किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के कब्जे से 130 ग्राम अल्प्राजोलम टैबलेट बरामद होने की बात कही गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50, 52-क और 42 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है और आवेदक का पांच मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसे पूरक शपथ पत्र में उचित रूप से स्पष्ट किया गया है और आवेदक 19.2.2026 से जेल में बंद है।

7. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 को संज्ञान में लेते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत के लिए मामला बना है। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपर्युक्त केस क्राइम में शामिल आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

24 मार्च, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।